भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1600
26 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारिता नीति

1600. श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति शुरू करने का प्रस्ताव किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार ने देश की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत के सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार, सहकारी समितियों के लिए एक नई राष्ट्रीय स्तर की नीति बना रही है। नई सहकारिता नीति पर सभी राज्यों के सहकारिता सचिवों/सहकारी समितियों के पंजीयकों के साथ दिनांक 12 व 13 अप्रैल, 2002 को दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिक ढांचा; नियामक, नीति व प्रचालनात्मक अवरोधों की पहचान; सुगम व्यापार; शासन सुदृढ़ करने हेतु सुधार; नए और सामाजिक सहकारी समितियों का संवर्धन; निष्क्रिय समितियों का पुनरुद्धार; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाना; सहकारी समितियों के बीच सहयोग और सहकारी समितियों के सदस्यों में वृद्धि करने पर विचार विमर्श किया गया।

इसके अलावा, प्रारूप नीति पर आम-जनता सहित हितधारकों से मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से सुझाव मांगे गए।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, संस्थानों और आम-जनता से प्राप्त टिप्पणियों तथा हितधारकों के साथ पुनः परामर्श के आधार पर नई नीति बनाई जाएगी।

- (ग): भारत के सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- i. दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने चीनी सहकारी मिलों को यह स्पष्ट करते हुए राहत प्रदान की है कि उन्हें उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) या राज्य सलाह मूल्य (एसएपी) तक, जैसा भी मामला हो, किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा।
 - ii. बजट घोषणा 2022 के अनुसार, सरकार ने 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए की कुल आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
 - iii. सूक्ष्म और लघु उद्यम की क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) की दिनांक 03 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस योजना के तहत विशिष्ट पात्रता मानदंड के साथ बतौर सदस्य उधारकर्ता संस्थान बनाया गया है। इससे सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण मिलने में सहायता मिलेगी जो सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति देगा।
 - iv. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 1 जून, 2022 की स्वीकृति के अनुसार, गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस- स्पेशल पर्पज वेहिकल (GeM-SPV) के अधिदेश को विस्तारित करते हुए जेम प्लैटफॉर्म पर बतौर क्रेता, सहकारी समितियों को पंजीकृत होने की अनुमति दी गई।
 - v. दिनांक 29 जून, 2022 को सरकार की स्वीकृति के अनुसार, सहकारिता क्षेत्र को पुनः सक्रिय करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के डिजिटलीकरण हेतु एक केन्द्र प्रायोजित योजना का अनुमोदन किया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ हो चुका है।
 - vi. पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई बनाने हेतु राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य हितधारकों की परामर्श से प्रारूप मॉडल उपनियम बनाए जा रहे हैं।
 - vii. सभी स्तरों पर सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के लिए हितधारकों के परामर्श से एक नई योजना- “सहकार से समृद्धि” बनाई जा रही है।
 - viii. उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप में सरकार को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य हितधारकों के परामर्श से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण किया जा रहा है।
 - ix. सहकारी क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण को आधुनिक और पेशेवर बनाने के लिए सभी हितधारकों के परामर्श से शिक्षण और प्रशिक्षण सहकारी संस्थानों को पुनःउन्मुख (रिओरिएंट) करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।